www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

सत्यमेव जयते

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 350

रोज़गार समाचार

साप्ताहिक

खण्ड 40 अंक 16 पृष्ठ 56 | नई दिल्ली 18 - 24 जुलाई 2015 | ₹ 8.00

स्मार्ट सिटी : भारतीय शहरों की तस्वीर बदलने की एक पहल

डॉ. रंजीत मेहता

इन दिनों स्मार्ट सिटी की बातें खूब चर्चा में हैं और ये सामान्य बातचीत का मूलमंत्र बन गया है. इस अवधारणा में मुख्य तौर पर एक सतत वातावरण के सृजन के लिये मानवीय पूंजी और प्रौद्योगिकी का संयोजन करना शामिल है. ऐसे शहर, स्थाई आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में कार्य करते हैं और नागरिकों के लिये उच्चतर गुणवत्ता के जीवन का भी निर्माण करते हैं क्योंकि उनका इस प्रक्रिया में योगदान होता है. शहरीकरण में हो रही वृद्धि के साथ ही भारत की शहरी जनसंख्या वर्ष 2031 तक बढ़कर 600 मिलियन हो जाने की आशा है. यह संख्या 2001 में शहरी जनसंख्या का लगभग दोगुना है. कुल मिलाकर पूरी जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगा. भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की भारतीय शहरी अवसंरचना और सेवाओं पर हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का शहरी हिस्सा वर्ष 2009-10 में करीब 62-63 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2030 में 75 प्रतिशत होने की आशा है. यही कारण है कि शहरों को ''आर्थिक विकास के इंजन'' के तौर पर संदर्भित किया जाता है. यह अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वे एक दक्ष इंजन के तौर पर कार्य करें, जैसा कि वे हमारे आर्थिक विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण है. शहरीकरण का ये रुझान, जो कि भारत में पिछले कुछ दशकों से नज़र आ रहा है, कुछ और समय के लिये जारी रहेगा.

वर्ष 2035 में कामकाजी जनसंख्या कुल जनसंख्या का क़रीब 69 प्रतिशत होगी. देश के आर्थिक विकास में शहरी क्षेत्रों का योगदान महत्वपूर्ण होगा और भविष्य की जनसंख्या के समायोजन के लिये उनका संपूर्ण विकास करना अपेक्षित होगा. इस बढ़ती शहरी जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिये भविष्य में शहरों की योजना बनाने और निवेश के लिये सतत वातावरण उपलब्ध करवाने, नये रोज़गारों और आजीविका के सृजन, विश्वसनीय सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करने, क़िफायती आवास की व्यापक पहुंच के साथ सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाने और सबसे महत्वपूर्ण

रूप से जीवन की सतत गुणवत्ता के लिये संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग को समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है. इस जबर्दस्त विकास से स्मार्ट शहरों के निर्माण में गति आयेगी, जिससे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से उत्पादकता बढ़ाकर लाइफ़स्टाइल और लोगों की खुशहाली बढ़ाने का अवसर मिलेगा. इसके अलावा हरित विकास रणनीतियों से शहरों में स्थाई पर्यावरण सुरक्षा का निर्माण हो सकता है. इस वर्ष 25 जून को प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में तीन प्रमुख शहरी विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ किया. ये हैं : एएमआरयूटी (कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिये अटल मिशन), स्मार्ट सिटी मिशन और सब के लिये आवास (शहरी). इसके साथ ही अगले पांच वर्षों के दौरान 100 स्मार्ट शहरों और 500 एएमआरयूटी शहरों के विकास और 2022 तक शहरी ग़रीबों के लिये दो करोड़ आवासों के निर्माण के लिये रोडमैप की शुरूआत हो गई है.

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि भारत में पहली बार एक ऐसी चुनौती पेश की जा रही है जिसमें शहरी भारत के नागरिक अपने शहरों का विकास अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप निर्धारित करने में योगदान कर सकते हैं. ऐसे शहरों का विकास स्मार्ट शहरों के तौर पर किया जायेगा, जो प्रतिस्पर्धात्मक तौर पर अपेक्षित दायरों को पूरा करने में समर्थ थे. अतः प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतिस्पर्द्धात्मक तंत्र से ऊपरी दृष्टिकोण का अंत होगा और लोक केंद्रित शहरी विकास पनपेगा. उन्होंने स्मार्ट सिटी का एक सामान्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो कि लोक आकांक्षाओं से एक-दो कदम आगे का था. श्री मोदी ने जिन बातों का उल्लेख किया उनमें प्रौद्योगिकी, परिवहन, ऊर्जा दक्षता, कामकाज के लिये आना-जाना, साइकिलिंग आदि कई चीजें शामिल थीं. स्मार्ट शहर लागत और संसाधनों के उपभोग में कमी लाने और अपने नागरिकों के साथ अधिक प्रभावकारी और सक्रियता के साथ जुड़ने के वास्ते शहरी सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यनिष्पादन को बढ़ाने के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों अथवा सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का इस्तेमाल करते हैं. स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी के विकास से जुड़े क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं का प्रबंधन, परिवहन और यातायात प्रबंधन, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, जल एवं कचड़ा प्रबंधन शामिल हैं. स्मार्ट सिटी अनुप्रयोग का विकास शहरी प्रवाहों के प्रबंधन में सुधार और चुनौतियों से सही समय में निपटने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. अतः एक स्मार्ट शहर अपने नागरिकों के साथ सामान्य व्यवहार संबंध की अपेक्षा चुनौतियों से निपटने के लिये अधिक तैयार होता है. बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों ने स्मार्ट शहरों में दिलचस्पी पैदा करने का काम किया है, जिनमें जलवायु परिवर्तन, आर्थिक पुनर्गठन, वाणिज्य और मनोरंजन क्षेत्र शामिल हैं.

(शेष पृष्ठ 56 पर)

रोज़गार सारांश

ओ.आई.सी.एल.

ओरियण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली को 606 सहायकों की आवश्यकता
अंतिम तिथि : 28.07.2015 (पृष्ठ 40)

ईस्टर्न नेवल कमांड

ईस्टर्न नेवल कमांड, विशाखापत्तनम को 219 अधीक्षक और भंडारपाल की आवश्यकता.
अंतिम तिथि : 31.08.2015 (पृष्ठ 50)

गन एवं शैल फैक्टरी

गन और शैल फैक्टरी, कोसीपोर, कोलकाता को 190 मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, इलेक्ट्रिशियन आदि की आवश्यकता
अंतिम तिथि : प्रकाशन की तिथि से 21 दिन (पृष्ठ 9)

कॉनकॉर

कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को 185 सहायक पर्यवेक्षक, वरिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर ग्रेड-I की आवश्यकता.
अंतिम तिथि : 10.08.2015 (पृष्ठ 47)

बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सशस्त्र सेनाओं, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों की अन्य रिक्तियों के लिए अंदर के पृष्ठ देखें.

वेब विशेष

www.rojgarsamachar.gov.in पर वेब विशेष खण्ड के तहत निम्नलिखित आलेख उपलब्ध है:-

- सभी स्कूलों में शौचालय

www.facebook.com/yojanaJournal
www.facebook.com/publicationsdivision

Follow us on: @Employ_News

Visit our facebook page
facebook.com/director.employmentnews

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में कॅरिअर के अवसर

ऋचा मित्रा

''यदि आप किसी व्यक्ति को एक मछली देते हैं तो आप उसे एक दिन का भोजन देते हैं... किंतु यदि आप किसी व्यक्ति को मछली पकड़ना सिखाते हैं तो आप उसे जीवन-भर भोजन देते हैं.''

भारत जैसे देश में निर्धन व्यक्ति पहले से मछली पकड़ना जानते हैं, उन्हें केवल थोड़ी-सी पूंजी की आवश्यकता होती है एक बोट जाल खरीदने के लिए माइक्रोफाइनेंस नामक एक परिवर्तनकारी वित्तीय मॉडल के आविर्भाव के पीछे यही प्रेरणा है, जो निर्धनों को, बैंकों जैसी स्थापित वित्तीय संस्थाओं से औपचारिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने में उनकी अक्षमता को ध्यान में रखते हुए, उनकी निजी अजीविका प्राप्त करने के अवसर देने के लिए उन्हें ऋण तथा बीमा के रूप में माइक्रोक्रेडिट देने के लिए बना है.

इस माइक्रोक्रेडिट मॉडल की सफलता से न केवल कई माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एम.एफ.आई.) तथा उनके विभिन्न मॉडल उन्नति करेंगे, बल्कि लाभ संभावना को पूंजी में परिणत करने के लिए अनेक बैंक इस क्षेत्र में प्रवेश तथा सक्रिय सहयोग भी करेंगे. सामाजिक निवेशकर्ता तथा व्यावसायिक निवेशकर्ता के बीच प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग ने स्नातकों और व्यवसायियों-दोनों के लिए रोज़गार के अवसर खोल दिए हैं.

इस क्षेत्र को, माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं में परिचालन, वित्त, मानव संसाधन, आंतरिक लेखा परीक्षा तथा कॉर्पोरेट संचार जैसे विभिन्न स्तरों पर किसी संगठन में कार्य करने के लिए विभिन्न शैक्षिक और अनुभव की पृष्ठभूमि रखने वाले कार्मिकों की आवश्यकता होती है.

किसी भी अन्य कार्य की तुलना में कार्य के अधिक अवसर अधिकांशतः परिचालन क्षेत्र में होते हैं, जहां किसी व्यक्ति को विभिन्न स्व-सहायता समूहों में जाने, उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को समझने और उसके बाद सभी प्रलेखन कार्य पूरा करने के बाद उन्हें अपेक्षित ऋण राशि वितरित करने का कार्य करना होता है.

माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं, अपने व्यवसाय मॉडल को अधिक धारणीय बनाने के लिए अपनी गैर-सरकारी संगठनों की स्थिति को विनियमित वित्तीय संस्थाओं के रूप में परिवर्तित कर रही हैं. प्रतिभा एवं पदारोहण का

मामला महत्वपूर्ण है. ये संस्थाएं नई सेवाएं देती हैं और उन्हें अपने संगठनों में व्यवसायवाद का स्तर बढ़ाना होता है. इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं- बंधन (**www.bandhanmf.com**), एस.के.एस. माइक्रोफाइनेंस (**www.sksindia.com**), इक्विट्स (**www.equitasmf.in**), उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेस (**www.ujjivan.com**), अर्थ माइक्रोफाइनेंस (**www.arthmicrofinance.com**).

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में कार्य का मुख्य रूप से बल प्राथमिक महिलाओं सहित गरीब परिवारों को क्रेडिट देने पर होता है, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके, समाज सेवा तथा ग्रामीण विकास की अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति इस क्षेत्र में अत्यधिक वांछित होते हैं. कार्य मुख्य रूप से विश्लेषिक प्रकृति के होते हैं, जिसमें अंग्रेजी, हिन्दी तथा आबंटित स्थान की स्थानीय भाषा में उत्कृष्ट अंतर-वैयक्तिक संचार क्षमता की भी आवश्यकता होती है. इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों से उनके कार्य-परिवेश में आ रहे परिवर्तनों से अद्यतन बने रहने की अपेक्षा होती है, जिसके लिए औसत से अधिक बौद्धिक क्षमता भी अपेक्षित होती है.

महत्वपूर्ण परिचालन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति क्रेडिट ऑफिसर के पद से कार्य प्रारंभ करके क्षेत्रीय प्रबंधक या निदेशक, परिचालन के स्तर तक पहुंच सकता है. क्रेडिट ऑफिसर के रूप में एंट्री स्तर के पदों पर वेतन 10000 से 15000 रु. तक होता हे, जो मध्य प्रबंधन पदों पर 45000 से 50000 रु. तक तथा वरिष्ठ स्तरीय पदों पर 80000 रु. तक हो सकता है.

माइक्रोफाइनेंस के क्षेत्र में कॅरिअर के विभिन्न अवसर इस प्रकार हैं:-

ऋण/क्रेडिट अधिकारी: ऋण/क्रेडिट अधिकारी का कार्य ऋण के आवेदनपत्रों का सत्यापन करके कार्रवाई करना तथा शाखा प्रबंधकों के अनुमोदन के लिए उनकी सिफारिश करना, ऋण वितरित करना तथा ऋण के वास्तविक उपयोग का सत्यापन करना, ग्राहक समूह बैठकों में भाग लेना, ऋण वसूली एकत्र करना एवं रिकॉर्ड करना, ऋण की उपयुक्त तथा सामयिक वसूली सुनिश्चित करना, विनियमन के लिए ओवरड्यू पर अनुवर्ती कार्रवाई करना, लेखा देखभाल एवं शाखा सॉफ्टवेयर के माध्यम से एंट्री करना और बैंकिंग लेन-देन का हस्तन करना है.

इस पद के लिए योग्यता स्नातक या हायर सेकेंडरी है. (आयु 18 से 30 वर्ष) स्थानीय भाषा में धारा प्रवाह होना आवश्यक है. उम्मीदवार टीम प्लेयर होने के साथ गरीबों तथा समाज के लिए कार्य करने का इच्छुक होना चाहिए; उम्मीदवार बुनियादी कम्प्यूटर-कौशल रखता हो,

(शेष पृष्ठ 56 पर)

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल-एसडब्ल्यू-1/4100/2015-17 यू (सी) 107/2015-17 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई. 28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 18/20.7.2015 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 16.07.2015

श्रीनगर, लेह, कालिमपोंग, इम्फाल, दीमापुर, अगरतला, दुलियाजॉन, करीमगंज, छाबुआ, दीफू, डिब्रूगढ़, तेजपुर, हेल्लाकांडी, मरियानी, जोरहाट, शिलांग, डिगबोई, सिल्चर तथा पोर्टब्लेयर के लिए विमान सेवा 20 पैसे अतिरिक्त

स्मार्ट सिटी: भारतीय शहरों...

(पृष्ठ 1 का शेष)

स्मार्ट शहरों को मुख्यत: तीन प्रकार के शहरों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(1) नये शहर
(2) वर्तमान शहरों का आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ पुन:संयोजन
(3) उद्देश्य संचालित शहर. नये शहरों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिये नागरिकों और व्यवसायियों को आकृष्ट करने हेतु सभी पहलुओं को आईसीटी से जोड़ना.

वर्तमान शहरों का स्मार्ट शहरों में पुन:संयोजन एक स्मार्ट शहर के सृजन के संपूर्ण उद्देश्य को हासिल करने के वास्ते पुरानी प्रणालियों को नयी प्रक्रियाओं के साथ जोड़ने का कदम दर कदम प्रयास है. उद्देश्य संचालित शहर उद्योग केंद्रित हो सकते हैं जिनका विज्ञान कस्बों अथवा अन्य प्रमुख गतिविधियों के इर्दगिर्द निर्माण किया जाता है. इस प्रकार के प्रत्येक शहर का पैमाना बहुत ऊंचा हो सकता है. यद्यपि सभी स्मार्ट शहरों में मुख्य रूप से आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) से जुड़ी परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं, जिनमें ऊर्जा, परिवहन, स्मार्ट भवनों, गवर्नेंस एवं सामाजिक अवसंरचना जैसे घटक शामिल होते हैं.

आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) में स्मार्ट शहरों के लिये आधारभूत हितैशी प्रणाली शामिल होती है और इसे प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता हासिल करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाता है. इसे विद्युत के इस्तेमाल और वितरण में सुधार, 24/7 जलापूर्ति सुनिश्चित करने, कुशल परिवहन और यातायात प्रबंधन के जरिये आवागमन व्यवस्था में सुधार, स्वचालित निगरानी और सुरक्षा प्रणाली में वृद्धि और बिजनेस के लिये वाई-फाई युक्त खुले स्थानों और आवास की उपलब्धता में सुधार के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे दुर्लभ संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग और उपलब्ध सेवाओं की सही समय पर निगरानी कार्य में भी सुधार हो सकता है. इसमें आपातस्थितियों में तेज़ी से कार्रवाई किये जाने की क्षमता भी मौजूद रहती है. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के एकीकरण की संभावनाएं असीमित हैं और ये मुख्यत: धन की उपलब्धता और विभिन्न शहरों के लिये निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों पर निर्भर करती हैं.

स्मार्ट शहर कुल कार्बन मात्रा को घटाने के लिये प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिये योजनाएं तैयार करते हैं. कुछ प्रमुख कार्यसूचियों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

नवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल: स्मार्ट शहर में पर्यावरण सुरक्षा के लिये ऊर्जा उत्पादन हेतु कोयले पर निर्भरता घटाने के लिये विद्युत के नवीकरणीय स्रोतों की आवश्यकता होती है.

विविध प्रयोग विकास कार्यों और पैदल चलने को प्रोत्साहन देना: स्मार्ट शहरों में पैदल चलने वाले समुदाय शामिल होते हैं, जहां अधिकतर मामलों में थोड़ी-थोड़ी दूरियां पैदल चलकर, साइकिल अथवा सार्वजनिक परिवहन के जरिये पूरी कर ली जाती हैं.

संसाधनों के अपव्यय में कमी: संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से स्मार्ट शहरों में पानी, बिजली आदि जैसे संसाधनों के स्रोत की पहचान और शोधन से इनका अपव्यय कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है. स्मार्ट शहर के लिये विद्युत पर इनकी अधिक निर्भरता होने के कारण दक्षतापूर्ण ऊर्जा प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है. ऊर्जा प्रबंधन के लिये लागू की गई कुछेक प्रौद्योगिकियों में स्मार्ट मीटरिंग, क्लाउड कम्प्यूटिंग और वायलैस कनेक्टिड सेंसर्स शामिल हैं. स्मार्ट मीटरों से उपयोगिता प्रदाताओं के साथ-साथ अंतिम उपयोगकर्ता तक खपत और व्यस्ततम लोड के घण्टों की खपत के संबंध में दोतरफा निगरानी की सुविधा होती है. इन प्रणालियों से नागरिकों को अपने प्लान टैरिफों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलती है.

इसके अलावा स्मार्ट शहर 'स्मार्ट ग्रिडों' का भी इस्तेमाल करते हैं. ये ऐसे पावर ग्रिड हैं जो कि कन्ट्रोल्स, ऑटोमेशन और नई प्रौद्योगिकियों से जुड़े होते हैं जिससे विद्युत का दक्षतापूर्ण पारेषण, विद्युत आपूर्ति के ठप्प होने अथवा अन्य घटनाओं के दौरान तेज़ी से आपूर्ति की बहाली, कुल प्रचालन और प्रबंधन लागत में कमी, और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का एकीकरण सुनिश्चित होता है. इसके अतिरिक्त वे उपभोक्ताओं को व्यस्ततम समय से भिन्न बिजली की मांग के लिये प्रोत्साहन देते हैं. कुल मिलाकर स्मार्ट ग्रिड जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के साथ-साथ ऊर्जा बचत के अवसर प्रदान करते हैं.

स्मार्ट शहर रेल, मेट्रो, बस और गैर-मोटरयुक्त परिवहन (पैदल चलना और साइकिलिंग) सहित विभिन्न पद्धतियों के अंतर्गत निर्बाध समन्वित सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क उपलब्ध करवाते हैं. दरअसल परिवहन के संबंध में नागरिकों की पहुंच को बढ़ाने और वास्तविक समय की निगरानी के वास्ते परिवहन नेटवर्क को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाता है. यातायात की चुनौतियों से निपटने और आवागमन में सुधार के वास्ते निर्देशित पार्किंग और वॉल्यूम-आधारित यातायात नियंत्रण प्रणालियां मदद करती हैं.

भारत में दस लाख से अधिक आबादी के 50 शहर हैं. रोज़गार सृजन के लिये नये शहरों की आवश्यकता है क्योंकि इससे लोगों को रोज़गार के लिये ले जाने की वर्तमान लघु अवधि विचारधारा को बदलकर लोगों तक रोज़गार ले जाने के अधिक सतत समाधान में परिवर्तित होगी. अगले 20 वर्षों में एक मजबूत क्षेत्रीय असमानता होने वाली है, भारत के दक्षिण और पश्चिम में पांच राज्य (गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश) देश के जीडीपी में 50 प्रतिशत का योगदान दर्शायेंगे, परंतु जनसंख्या वृद्धि केवल 5 प्रतिशत ही दर्शायेंगे. हमें शहरीकरण को ध्यानपूर्वक परिभाषित करना चाहिये, यह अधिक लोगों को बड़े शहरों में पुनर्स्थापित करना नहीं है और न ही यह चंडीगढ़ जैसी सुनियोजित आर्थिक बंजर भूमि की तरह है. हमने दिल्ली के निकट गुड़गांव, हैदराबाद के निकट गच्चीबावली, पुणे के निकट मागरपाट्टा, बंगलुरू के निकट व्हाइटफील्ड और चंडीगढ़ के निकट मोहाली जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सफलता के छोटे-छोटे नमूने देखे हैं, परंतु ये स्मार्ट शहरों की पहचान से बहुत दूर हैं.

भारत के बड़े महानगरों के बीच औद्योगिक कोरीडोर्स, जैसे कि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरीडोर, चेन्नई-बंगलौर औद्योगिक कोरीडोर और बंगलुरू-मुंबई आर्थिक कोरीडोर एक सकारात्मक पहल के तौर पर दिखाई देते हैं. यह आशा की जाती है कि इन क्षेत्रों के साथ लगते कई औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों का स्मार्ट शहरों के तौर पर पुनर्निर्माण किया जायेगा. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरीडोर (डीएमआईसी) के तहत, जो छह राज्यों के भीतर फैला है, इसके पहले चरण में सात नये स्मार्ट शहरों के विकास की बात कही गई है. स्मार्ट शहरों के पीछे की अवधारणा का आधार इस बात में निहित है कि इनके जरिये नागरिकों के सामने पेश आने वाली सामान्य समस्याओं के लिये प्रौद्योगिकीय समाधान मौजूद हैं. अदक्षता की समस्याएं, जो कि पुरानी ब्यूरोक्रेटिक-राजनीतिक प्रक्रिया में पाई जाती हैं, उन्हें 'बड़े विवरण' तैयार करते हुए 'स्मार्ट' समाधान उपलब्ध कराया जाना है. 'स्मार्ट शहरों' का एक अन्य सकारात्मक प्रभाव रोज़गार सृजन का है और कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्षेत्र 'स्मार्ट' हो जायेगा. यद्यपि सृजित होने वाले रोज़गार और श्रमिक विस्थापन में कमी का अनुमान लगाना कठिन है लेकिन कोई भी विश्वास के साथ कह सकता है कि यदि अगले एक वर्ष के दौरान 10-15 स्मार्ट शहरों में भी काम आरंभ होता है तो हम कई हजार रोजगारों के लिये अनुकूल पारिस्थितिकी प्रणाली तैयार कर पायेंगे. इससे सब के लिये रोज़गार के अवसर सृजित होंगे परंतु किसी भी स्मार्ट शहर की रीढ़ आईटी अवसरंचना होने की वजह से आई टी विशेषज्ञों के लिये रोज़गार के अवसरों की संख्या कुछ अधिक हो सकती है. इसके लिये डाटा विश्लेषण, प्रोग्रामिंग, उच्च स्तरीय कन्सलटिंग कार्य, सिस्टम और नेटवर्क संयोजन जैसे कार्यों के लिये अधिक मांग होगी और इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ और छात्र बेहतर अवसरों की आशा कर सकते हैं. यह इंटरनेट युग के लिये महान अवसर और समय हो सकता है. शहरी जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही हमारी जनसंख्या की बढ़ती शहरी आकांक्षाओं को पूरा करने के वास्ते बुनियादी ढांचा सुविधाओं के सृजन की तत्काल आवश्यकता है और इसका समाधान स्मार्ट शहर हो सकते हैं. अब जबकि फ़ोकस स्मार्ट शहरों और शहरीकरण की तरफ हो गया है, इस बात को सुनिश्चत किये जाने पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि हमारी जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत जो अकुशल रोज़गारों और कृषि पर निर्भर करता है, कहीं पीछे न छूट जाये.

(लेखक डॉ. रंजीत मेहता निदेशक, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली से हैं)
ई-मेल-ranjeetmehta@phdcci.in

न्यूज़ डाइजेस्ट

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समयबद्ध ढंग से संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है. रूस के ऊफा शहर में ब्रिक्स नेताओं के पूर्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास और जलवायु परिवर्तन विश्व के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र को निर्णायक भूमिका अदा करनी है. उन्होंने ब्रिक्स देशों में आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए सभी देशों से एकजुट होकर प्रयास करने की मांग की. श्री मोदी ने ब्रिक्स कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव किया और एक ऐसा मंच बनाने का सुझाव दिया जो सदस्य देशों के बीच अनुभवों के अदान-प्रदान में स्थानीय सरकारों के साथ संपर्क कर सकें.
- भारत और पाकिस्तान ने अवरुद्ध वार्ता प्रक्रिया को बहाल करने और मुंबई आतंकी हमला मामले की सुनवाई तेजी से करने के उपाय करने का निर्णय किया है. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शिखर बैठक के अवसर पर रूस के ऊफा शहर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच करीब एक वर्ष बाद हुई पहली द्विपक्षीय वार्ता में दक्षिण एशिया से आतंकवाद खत्म करने के उपायों में सहयोग करने पर सहमति हुई. दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच बकाया सभी मुद्दों पर विचारों का अदान-प्रदान किया.
- ब्रिक्स नेताओं ने एक तरफा सैन्य हस्तक्षेपों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की प्रवृत्तियों की निंदा की है. ऊफा, रूस में जारी घोषणा में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने सुरक्षा के अभिभाज्य स्वरूप के बेजोड़ महत्व पर प्रकाश डाला. घोषणा में कहा गया कि किसी राष्ट्र को अन्य राष्ट्र की कीमत पर अपनी सुरक्षा मजबूत नहीं करनी चाहिए.
- भारत और कजाकिस्तान ने रक्षा और सैन्य सहयोग, संस्कृति और खेलों, रेलवे, सजायाफ्ता व्यक्तियों की अदला बदली, और भारत को यूरेनियम की आपूर्ति के बारे में पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इन समझौतों पर अस्टाना में प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नज़र की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए.
- भारत और अमरीका ने विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम को लागू करने के बारे में अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता कर सम्बन्धी मामलों में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और दोनों देशों के बीच सूचना के अदान-प्रदान के जरिये अंतर्राष्ट्रीय कर वंचना की समस्या को दूर करेगा.
- रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए तीन परियोजनाएं शुरू की हैं. ये हैं नेक्स्ट जेनरेशन ई-टिकिटिंग, हिन्दी वेबसाइट, मुंबई उपनगरीय ट्रेन के लिए मोबाइल फोन के जरिये कागज रहित अनारक्षित टिकटिंग और राजधानी तथा दुरंतो रेल गाड़ियों में एसएमएस के जरिये डेस्टिनेशन एलर्ट सर्विस.
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने देश में पहली बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पूर्वोत्तर अध्ययन में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम शुरू किया है. इससे भारत की मुख्य भूमि और पूर्वोत्तर के बीच दूरी कम करने में मदद मिलेगी.
- केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय ने उद्योग जगत की कुशल कार्मिकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं. इन समझौतों से दोनों मंत्रालयों के बीच कार्यनीतिक सम्बन्ध सुदृढ़ होंगे ताकि देश में कौशल विकास और उद्यमशीलता के उपायों को बढ़ावा दिया जा सके.

विंडो विज्ञापन के बारे में नोटिस

दूर-दराज़ के क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों में बेरोज़गार युवाओं को नौकरियों/प्रशिक्षण/ शैक्षिक अवसरों से संबंधित जानकारी प्रदान करना रोज़गार समाचार का लक्ष्य रहा है.

सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विज्ञापनदाताओं से अनुरोध है कि वे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/ रोज़गार समाचार में प्रकाशन के लिए विस्तृत विज्ञापन भेजें, जिनमें पदों की संख्या, आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और आवेदन करने की पद्धति आदि के बारे में जानकारी हो, ताकि आवेदकों को सम्बद्ध रिक्तियों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके. आधे-अधूरे या अस्पष्ट विज्ञापन रोज़गार समाचार/एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं किए जायेंगे.

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में...

(पृष्ठ 1 का शेष)

आत्म- विश्वास, संचार कौशल, विश्वासोत्पादक क्षमता से सम्पन्न हो और स्वाग्रही हो.

शाखा प्रबंधक

शाखा प्रबंधक का कार्य कार्मिकों की भर्ती करने, शाखाओं की स्थापना करने, अल्पकालिक योजनाएं बनाने एवं कार्यान्वित करने, व्यवसाय योजना लक्ष्यों को पूरा करने क्षेत्र में मसलों का समाधान करने, शाखा को कड़े अनुशासन एवं एक प्रभावी तरीके से चलाने सहित किसी एकक में सभी क्षेत्रगत परिचालन कार्यों पर निगरानी रखना है. उम्मीदवार सामाजिक विज्ञान/प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री तथा वरीयतः माइक्रोफाइनेंस संस्था में कार्य का योग्यता विशिष्ट अनुभव (कम से कम 4 वर्ष) रखता हो. उम्मीदवार का एक दल का नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो. वह ओजस्वी, उत्साही तथा विक्रय-प्रेरित होना चाहिए.

क्षेत्र-प्रबंधक

क्षेत्र प्रबंधक अपने क्षेत्रों के अंतर्गत सभी शाखाओं के परिचालन के लिए जिम्मेदार होता है. उसके क्षेत्र में न्यूनतम 8 से 10 शाखाएं उसके अधीन हो सकती हैं, जिनके शाखा प्रबंधन उसे रिपोर्ट करते हैं.

वह सम्पूर्ण शाखा निष्पादन एवं लाभकारिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है और वह रीजनल प्रबंधक को रिपोर्ट करता है.

उम्मीदवार सामाजिक विज्ञान/प्रबंधन में स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री रखता हो और माइक्रोफाइनेंस संस्था में कार्य करने का अनुभव (वरीयतः न्यूनतम 06 वर्षों का अनुभव रखता हो.

क्षेत्रीय प्रबंधक

क्षेत्रीय शाखा प्रबंधक अपने क्षेत्र की सभी शाखाओं के परिचालन के लिए जिम्मेदार होता है. उसके अधीन कम से कम 20 से 30 शाखाएं हो सकती हैं और क्षेत्र-प्रबंधक/शाखा प्रबंधक उसे रिपोर्ट करते हैं.

वह सामाजिक विज्ञान/प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री रखता हो. एम.बी.ए. योग्यता को वरीयता दी जाती है. उम्मीदवार माइक्रोफाइनेंस संस्था में कार्य करने का अनुभव (वरीयतः न्यूनतम 8 से 10 वर्ष का) रखता हो तथा एक बड़े दल का नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए.

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में कॅरिअर समाज के निर्धन वर्ग की, उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना कर सेवा करने की एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि देता है. इसके अतिरिक्त, यह आप को एक व्यवसायी के रूप में वित्तीय समर्थन तथा उन्नति का आश्वासन भी देता है, जो स्वयं कॅरिअर का एक अच्छा विकल्प सिद्ध होता है.

[लेखिका जे.आई.एम.एस., जयपुर में सहायक प्रोफेसर हैं]
ई-मेल: richamitra@gmail.com

रोज़गार समाचार

पुष्पेंदर कौर (महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक)
डॉ. ममता रानी (संपादक)
हसन जिया (वरिष्ठ संपादक)
अयिनीडि वेंकटप्पय्या (संपादक विज्ञापन)
दिव्यांशु कुमार (संपादक)
वी. के. मीणा (संयुक्त निदेशक) (उत्पादन)
संदीप निगम (उत्पादन अधिकारी)
पी.के. मंडल (वरिष्ठ कलाकार)
के.पी. मणिलाल (लेखा अधिकारी)
जगदीश चंद्र जायसवाल (व्यापार कार्यपालक) (वितरण)

ई-मेल-महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक
director.employmentnews@gmail.com
विज्ञापन : enewsadvt@yahoo.com

संपादकीय :	: 26163055
विज्ञापन	: 26104284
टेलीफैक्स	: 26193012
वितरण	: 26107405
टैलीफैक्स	: 26175516
प्रोडक्शन	: 26177529
लेखा (विज्ञापन)	: 26193179
लेखा (वितरण)	: 26182079

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए **डॉ. साधना राउत,** अपर महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी-21 व 22, सेक्टर-59, नोएडा-201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक-IV, लेवल-5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 द्वारा प्रकाशित, संपादक: डॉ. ममता रानी